



वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हालिया वर्षों में ब्राजील के एमेज़ॉन क्षेत्र की पक्षी प्रजातियों के साथ कुछ अजीब घट रहा है। ना केवल पक्षियों की संख्या कम हो रही है बल्कि उनके शरीर का आकार भी घट रहा है। मुख्य शोधकर्ता, लूसिएना स्टेट युनिवर्सिटी के विटेक जिरिनेक ने बताया, "हमने देखा कि कुछ संवेदनशील प्रजातियों का ही नहीं बल्कि हरेक प्रजाति के पक्षियों का आकार कम हो रहा है।" जिरिनेक का यह शोध हाल ही में जर्नल साइंस एडवॉन्स में छपा है। जिरिनेक के सुपरवाइज़र फिलिप स्टीफर ने कहा कि, इस शोध में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो यह कि यह सब विश्व के सर्वाधिक संरक्षित ट्रॉपिकल वर्षावनो में हो रहा है। शोध में 40 साल की अवधि में 77 प्रजातियों का अध्ययन किया गया। चित्र में नज़र आ रहा पक्षी, रिड एटर्नलपिट भी शोध में शामिल था। इस अवधि में वर्षावनो का तापमान भी बढ़ा है। शोध में सामने आया कि पक्षियों का तेजी से उद्विकास हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि छोटे पक्षी ज्यादा अच्छी तरह उष्मा उत्सर्जित करते हैं। युनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ब्रायन वीक्स इस अध्ययन में शामिल नहीं थे, पर वे उत्तरी अमेरिका में प्रवासी पक्षियों की 50 प्रजातियों पर शोध कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने भी यही पाया कि लगभग सभी प्रजातियों का आकार कम हो रहा है। इन दोनों अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि दुनियाभर के पक्षी, चाहे वे प्रवासी हों या ना हों, उनका आकार बदल रहा है और इसका कारण है गर्म होती जलवायु। वीक्स कहते हैं, "इस प्रकार के परिवर्तन हम सबके लिए चिंताजनक हैं।"

## ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण की समीक्षा रिपोर्ट तीन सप्ताह में पेश होगी

केन्द्र सरकार ने तीन सदस्यीय समिति गठित ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के मानकों की विस्तृत अध्ययन एवं समीक्षा रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा

नई दिल्ली, 30 नवम्बर। केंद्र सरकार ने देश में इकोनोमिकली वीकर सैक्शन (ई.डब्ल्यू.एस.) आरक्षण के मानकों की समीक्षा के लिए मंगलवार को तीन सदस्यीय समिति गठित की। इसका प्रमुख पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय को बनाया गया है। सरकार ने समिति से आग्रह किया है कि, कमेटी तीन सप्ताह में काम पूरा कर रिपोर्ट पेश करे। गौरतलब है कि, गत गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित आठ लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के मानदंड पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। इस संबंध में चार सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा के लिए समिति का गठन इसी सिलसिले में अगला कदम माना जा रहा

है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता

- गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की सालाना आय वाले व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर मानने पर एतराज जाहिर किया था और सरकार को ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के मानकों की समीक्षा करने का निर्देश दिया था।
- इस समिति का प्रमुख पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय को बनाया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्या हर माह 70 हजार रुपये कमाने वाले को आर्थिक रूप से कमजोर माना जा सकता है।

### संयुक्त किसान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रहे हैं। मोर्चा के सूत्रों ने कहा कि हालांकि यह मुद्दा एस.के.एम. में विचाराधीन है कि आगामी विधानसभा चुनावों में किसान संगठन भाग लें अथवा नहीं, लेकिन अभी तक मोर्चा ने चुनावों में कूदने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि एस.के.एम. के नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली के किसी एक सीमा पर शनिवार को होगी, जिसमें आंदोलन को समाप्त करने के बारे में विचार किया जायेगा, क्योंकि सोमवार को, संसद में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का विधेयक पारित हो गया है, लेकिन "किसान एकता मोर्चा" जो एस.के.एम. की इन्टरनेट-उपस्थिति को संचालित करता है, ने मंगलवार को ट्वीट किया कि अगर किसानों को एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी मिल जाती है तो किसान दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी को हटकर, अपने-अपने घर लौट सकते हैं।

ट्वीट में कहा गया, "कृषि कानूनों को वापसी के बाद, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, किसानों की मांग है- एम.एस.पी. की (कानूनी) गारंटी। सरकार को इस मांग पर ध्यान देकर इसे पूरा करना चाहिये।"

किन्तु अन्य किसान नेताओं का कहना है कि वे बुधवार को मीटिंग में इस बात पर जोर देंगे कि सरकार उन 700 किसानों के परिवारों को हर्जाना दे, जिन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जान गँवाई है तथा इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में किसानों के खिलाफ लगे क्रिमिनल केस वापस लिये जायें।

### महासचिव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उन तक पहुंच नहीं बन पाती और हिंदी भाषी क्षेत्रों से आने वालों के लिए भाषा की भी समस्या हो जाती है। अब यह देखना है कि राहुल गांधी जीती मक्खी निगलते हैं या वेणुगोपाल का समर्थन करना जारी रखते हैं।

दी जाएगी, जब तक कि ईडब्ल्यूएस मानदंड पर नया निर्णय नहीं लिया जाता है। उन्होंने कहा, मुझे यह कहने का

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रगतिशील और व्यावहारिक आरक्षण है और एकमात्र सवाल यह है कि यह किस तरह से लाया हो। याचिकाकर्ताओं के वकील अरविंद दातार ने कहा कि सवाल यह है कि क्या प्रति माह 70,000 रुपये की आय को ईडब्ल्यूएस कहा जा सकता है। सीमा मुद्दे के पहलू पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि इस पर काम किया जा सकता है।

वाली पीठ को आश्वासन दिया था कि तीनों प्रवेश के लिए काउंसिलिंग चार सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर

निर्देश है कि सरकार ने मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है, हम चार सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे।

## उत्तराखण्ड देवस्थान बोर्ड भंग हुआ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर यह बोर्ड भंग करने के लिए भारी दबाव था

देहरादून, 30 नवम्बर (वार्ता)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देवस्थानम प्रबंधन परिषद (जेड) बंद करने की घोषणा कर दी। धामी ने टिवटर पर लिखा आप सभी की भावनाओं, तीर्थपुरोहितों, हक-हकूकधारियों के सम्मान एवं चार्धाम से जुड़े सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मनोहर कांत ध्यानी जी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने देवस्थानम बोर्ड अधिनियम वापस लेने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि, तत्कालीन त्रिवेन्द्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व वाली राज्य सरकार ने राज्य के गंगात्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित 53 देवस्थानों के प्रबंधन के लिये बोर्ड का गठन किया था। जिसका लगातार तीर्थ पुरोहितों और

हकूकधारियों द्वारा विरोध किया जा रहा था। त्रिवेन्द्र को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का कारण भी मुख्य रूप से इसी फैसले को समझा जा रहा था।

- गौरतलब है कि, गत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देवस्थान बोर्ड का गठन किया था और माना जाता है कि उनका मुख्यमंत्री पद भी इसी फैसले की वजह से भाजपा हाईकमान ने छीन लिया था।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों और हकूकधारियों द्वारा लगातार किये जा रहे विरोध और आगामी चुनावों को देखते हुये देवस्थान बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करने का फैसला किया है।

धामी की आज की घोषणा के बाद राज्य भर के तीर्थ पुरोहितों में प्रसन्नता का माहौल है। जबकि विपक्षी दलों ने इसे दैरे आये, दुरुस्त आये की संज्ञा देते हुये आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण इस फैसले को बताया है।

उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने को राज्य की भाजपा सरकार के मुंह पर करारा तमाचा

दरकिनार कर जिस तरह सरकार अपनी तानाशाही दिखाने में लगी थी वह उसका मुख्तारपूर्ण कदम था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव को देखते हुए सरकार अपने फैसले बदल रही है और सरकार को अगर रोलबैक सरकार कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब राज्य में चुनाव में मात्र तीन महीने रह गए हैं और कोई शक नहीं जिस दिन भी राज्य में चुनाव होंगे भाजपा कि राज्य में करारी हार होगी। प्रदेश कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धरमाना ने पंडा, पुरोहित, हक हकूकधारियों को बधाई देते हुये कहा कि प्रचंड बहुमत के अहंकार में डूबी भाजपा सरकार को आज दो वर्ष बाद इस कानून पर रोल बैक करते हुए देवस्थानम बोर्ड भंग करने की घोषणा करनी पड़ी। यह लोकतंत्र व जनता की जीत है।

## बंगाल के भाजपा नेता ने ममता बनर्जी पर तंज कसा

भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, सोनिया गांधी का समय पूरा हो चुका है, अब ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती हैं

कोलकाता, 30 नवम्बर। टी.एम.सी. प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने को देखते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर तंज किया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व बंगाल के नेता दिलीप घोष ने कांग्रेस-तृणमूल के बीच बढ़ते फासले को लेकर कहा कि सोनिया गांधी का समय पूरा हो चुका है। अब ममता बनर्जी विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती हैं। घोष ने यह भी कहा कि विपक्ष का ये नाटक काफी पुराना है। विपक्ष की हर पार्टी चाहती है कि वह नेतृत्व करे। ममता बनर्जी भी विपक्ष की नेता बनना चाहती हैं। दरअसल ममता बनर्जी बीते कुछ महीनों से दिल्ली से लेकर

में हिस्सा लिया और न ही केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के साथ शामिल

टी.एम.सी. पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस ने कहा था कि टी.एम.सी. किसानों के मुद्दे पर

- उन्होंने आगे कहा कि, यह नाटक बहुत पुराना है, हर छोटे से छोटी पार्टी की यही महत्वाकांक्षा है कि वह विपक्ष का नेतृत्व करे
- गौरतलब है कि, ममता बनर्जी एक संयुक्त विपक्ष मोर्चा खड़ा करने की कवायद में जुटी हुई हैं लेकिन वे इस पूरी कवायद से कांग्रेस को बिल्कुल अलग-थलग छोड़ देना चाहती हैं।

हुई। कांग्रेस ने यह बैठक शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की साझा रणनीति बनाने के लिए बुलाई थी। उधर, कांग्रेस की तरफ से

## सरकार फिर से किसान नेताओं से बातचीत शुरू करेगी

सरकार ने बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 किसान नेताओं के नाम मांगे

नई दिल्ली, 30 नवम्बर। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि मिनिमम सपोर्ट ग्राहस (एम.एस.पी.) और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए एक समिति गठित करने के लिए केंद्र ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से पांच नाम मांगे हैं। इसका फैसला किसान संघों संयुक्त इकाई यानी संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम. अपनी 4 दिसंबर की बैठक में करेगी।

यह कदम संसद के दोनों सदनों द्वारा तीन विवादस्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पारित करने के एक दिन बाद आया है, जिसके खिलाफ किसान एक साल से विरोध कर रहे हैं।

पाल ने बताया, "आज, केंद्र ने एसकेएम से उस समिति के लिए पांच नाम मांगे हैं जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) के मुद्दे पर विचार करेगी। हमने अभी तक नामों पर फैसला नहीं किया है। हम इसे 4 दिसंबर की बैठक में तय करेंगे।"

एसकेएम, 40 से अधिक फार्म यूनियनों की एक संयुक्त शाखा है, जो कि एम.एस.पी. के लिए कानूनी गारंटी

### निलंबित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) से "वॉकआउट" तथा पूरे दिन की बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने गांधी जी की मूर्ति के पास विरोध-प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के नेतृत्व में हुये इस वॉकआउट में तृणमूल कांग्रेस पहले तो शामिल नहीं हुई, लेकिन बाद में वह गांधी मूर्ति पर किये गये विरोध-प्रदर्शन में शामिल हो गई।

विश्व के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कक्ष में दिन में दूसरी बार एक सर्वदलीय मीटिंग आयोजित की, जिसमें यह महसूस किया गया कि पूरे सत्र के लिये किया गया निलम्बन उचित नहीं है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा कि पूरे सत्र का बहिष्कार करने से कोई एगोजन सिद्ध नहीं होगा, बल्कि विपक्ष को जनता के व्यापक हित के मुद्दों को उठाना चाहिये।

तृणमूल कांग्रेस के दो सांसदों के अलावा अन्य सभी निलंबित सांसद राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू को पत्र लिखेंगे तथा पत्र में सरकार द्वारा किये गये "प्रक्रिया के खुले एवं साफ उल्लेखनों" तथा "चयनाधारित सोच" के मुद्दे उठायेगे, जिन पर सुबह सदन में खड़गे ने भी उल्लेखनीय प्रकाश डाला था।

- भारतीय किसान यूनियन के नेता जोगेन्द्र नैन ने कहा कि, प्रधानमंत्री को हमारी ओर से जो छः मांगें भेजी गई थी, उस पर फैसले की घड़ी का इंतजार करें और शांति बनाए रखें। नैन ने कहा कि, हम किसान अपनी मांगें मनवाने के लिए आए हैं न कि सरकार से टकराने के लिए।

सहित तीन कृषि कानूनों और उनकी अन्य मांगों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पैटर्न बदलने और एम.एस.पी. को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान यह घोषणा की जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है, जो पिछले एक साल से किसानों के विरोध के केंद्र में थे।

जोगेंद्र सिंह नैन बीकेयू जॉर्द ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कॉल देगा, उसका हम पूरा पालन करेंगे। मुकदमे वापिस किए जाए। जिन किसानों

### पत्रकारों ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) रखी जाए। उनका कहना है कि सरकार ने पत्रकारों का वार्षिक अधिस्वीकरण जारी करना भी रोक रखा है और जो पत्रकार सरकार विरोधी प्रश्न पूछते हैं या सरकार की नीतियों व निर्णयों के खिलाफ लिखते हैं उनसे छुटकारा पाने की भी एक प्रक्रिया भी चल रही है। पत्रकारों के अधिस्वीकरण के नवीनीकरण की प्रक्रिया नवम्बर माह

की आंदोलन के दौरान जान गई है, उन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी दिल्ली कूच के दौरान जो ट्रैक्टर थानों में बंद है उन्हें छोड़ा जाए। नैन ने किसानों को कहा कि प्रधानमंत्री को जो छह मांगें भेजी गई थी, उस पर फैसले की घड़ी का इंतजार करें और शांति बनाए रखें। नैन ने कहा कि हम अपनी मांगें मनवाने के लिए आए हैं न कि सरकार से टकराने के लिए। राजनीतिक पार्टियां हमें भड़काने की कोशिश करेंगी।

में शुरू हो जाती हैं, लेकिन प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (पी.आई.बी.) ने पंजीकरण या अधिस्वीकरणों के नवीनीकरण के लिए अपनी बैकसाइट के एक-सैस को ब्लॉक कर दिया है तथा इसके 3 चक्र पत्रकारों से कहा गया है कि पत्रकारों और संगठनों की सरकार द्वारा स्क्रीनिंग के लिए वर्ष 2021 के ही पास मार्च माह के अंत तक वैध माने जाएंगे।

## राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर ट्रेलर-कार की टक्कर, तीन की मौत, 7 घायल

कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त, ट्रेलर सड़क से नीचे पलटा

राजसमन्द, 30 नवम्बर (निर्स)। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर दिवेर थानांतर्गत दराड़ा के समीप एक होटल के पास मोड़ पर मंगलवार सुबह पीने 8 बजे उदयपुर की तरफ से आ रही कार को सामने से आ रहे ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई जिसमे कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और सात लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से राजसमंद के जिला अस्पताल भेजा गया।

इधर मृतकों के शवों को देवगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। दुर्घटना के बाद दिवेर पुलिस ने ग्रामीणों, राहगीरों और क्रेन की सहायता से तत्काल प्रभाव से कार में फंसे घायलों और मृतकों को बाहर निकलवाकर मार्ग खुलवाया।

दिवेर थानाधिकारी दिलीप सिंह के

- घायलों को जिला अस्पताल भेजा और मृतकों के शवों को देवगढ़ सी.एच.सी. की मोर्चरी में रखवाया गया।

अनुसार गुजरात की तरफ से हरियाणा पाँसिंग एक जिनोन कार (केम्पर टाइप) आ रही थी जिसमें भटिंडा, पंजाब के 10 दोस्त सवार थे जो कि सम्भवतः पर्यटक थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेलर भी सड़क से एक तरफ खड़े में पलट गया। कार में सवार सभी लोग उसमें बुरी तरह फंस गए जिससे तीनों लोगों की तो मौतें कर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना

मिलते ही दिवेर थानाधिकारी दिलीप सिंह मय जापा के मौके पर पहुँचे और तत्काल प्रभाव से क्रेन मंगवाई। ट्रेलर चालक के मामूली चोटें आईं जिसे प्रथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। वहीं मौके पर ही मृत तीनों जनों के शवों को देवगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया और पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। पुलिस ने बताया कि मृतकों और घायलों के परिजनों के भटिंडा, पंजाब से यहाँ पहुँचने के बाद ही सभी लोगों की सही पहचान हो पाएगी।

मृतकों में जससा सिंह, सरणजीत सिंह, रामा सभी निवासी भटिंडा, पंजाब शामिल हैं। वहीं घायलों में सतवाल सिंह, सुखदी, नवदीप सिंह, अमनदीप सिंह, गुरविंदर सिंह, बलविंदर सिंह व एक अन्य जिसका नाम नहीं पता चला सभी निवासी भटिंडा, पंजाब शामिल है।

कश्मीर में देवी दुर्गा की 1300 साल पुरानी मूर्ति मिली

श्रीनगर , 30 नवंबर (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को मध्य कश्मीर में बडगाम जिले के खाग इलाके से देवी दुर्गा की 1300 साल पुरानी एक प्राचीन मूर्ति बरामद की। पुलिस ने बताया कि उन्होंने खाग से एक प्राचीन मूर्ति बरामद की और उसके बाद जम्मू-कश्मीर सरकार के अभिलेखागार, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की एक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मूर्ति की जांच करने के बाद बताया कि वह लगभग सातवीं ईस्वी (लगभग 1300 साल पुरानी) में निर्मित देवी दुर्गा की मूर्ति है। पुलिस ने एक बयान जारी करके बताया कि मूर्ति को काले पत्थर पर उकेरा गया है। यह मूर्ति देवी दुर्गा की है, जो सिंह सिंहासन पर विराजमान हैं, मूर्ति का बाँया हाथी कंधे से गायब है और दाहिने हाथ में कमल है। मूर्ति निर्माण में गांधार कला शैली का प्रभाव है।

‘क्रिप्टो करेन्सी के विज्ञापन पर रोक नहीं लगेगी’

नयी दिल्ली, 30 नवंबर (वार्ता)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्य सभा में कहा कि देश में आभासी मुद्रा (क्रिप्टोकॉरेंसी) से संबंधित विधेयक कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयेगी लेकिन क्रिप्टो को लेकर विधिभ्रम माध्यमों पर आ रहे विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान सदन में पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि यह एक जोखिम भरा है और यह पूरी तरह से नियामक फ्रेमवर्क भी नहीं है। इसके विज्ञापनों पर रोक लगाने का निर्णय भी नहीं लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के माध्यम से लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने की कोशिश की गयी है। उन्होंने कहा कि आभासी मुद्राओं से अवांछित गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए इस पर करीबी निगरानी की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इसके

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, सरकार क्रिप्टो करेन्सी पर एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्रिप्टो के साथ ही नये प्रावधान भी होंगे।

लिप एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है जिसमें पुराने विधेयक के साथ ही नये प्रावधान भी होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि कहा कि नॉन फिजिकल टोकन (एनएफटी) के नियम पर भी चर्चा की जायेगी। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि एनएफटी के नियम पर भी चर्चा ही जायेगी।